the roller flour mills to purchase the wheat to the extent possible. Connected facilities in the matter of transport and bank credit were extended to the mills.

घटिया बीजों की पूर्ति के संबंध में शिकायतें

807. **श्रीमती रेणुका चौधरी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को एसोसिएटेड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फाउन्डेशन द्वारा किसानों को घटिया बीज देने से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इन आरोपों की जांच की है; यदि हां, तो जांच के परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इन शिकायतों की जांच की जा रही है।

खाद्यान्न के रख-रखाव और उसके वहन संबंधी समिति

808. **श्रीमती रेणुका चौधरी :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने खाद्यान्न के रख-रखाव और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से संबंधित परिस्थितियों पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी ;

(ख) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त रिपोर्ट के अनुसार गत चार वर्षों में 18.41 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न रख-रखाव के दोषपूर्ण तरीके के कारण नष्ट हो गया है ;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस संदर्भ में सरकार द्वारा अब तक क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) खाद्यान्नों का अनुरक्षण करने तथा उनकी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढुलाई करने से संबंधित शर्तों पर विचार करने मात्र के लिए ही कोई समिति नियुक्त नहीं की गई थी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) खाद्यान्नों की हानियां दो शीर्षों अर्थात् (1) भंडारण, और (2) समुद्री मार्ग सहित मार्गस्थ के अन्तर्गत होती है। निगम को पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई हानियों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

(मात्रा लाख मीटरी टन में)

वर्ष	कुल खरीद+ बिक्री	कुल हानि	मूल्य करोड़ रुपये में	हानि की प्रतिशतता
1983–84	319.00	6.74	140.70	2.11
1984–85	295.14	5.72	122.76	1.94
1985–86	368.40	5.95	136.12	1.62
	982.54	18.41	399.58	

वर्ष 1986-87 के लिए लेखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

भारतीय खाद्य निगम ने हानियों को कम करने के लिए खाद्यान्नों की हैंडलिंग करने के स्थलों पर यथासम्भव 100 प्रतिशत तोल करने को सुनिश्चित करने, के लिये अतिरिक्त तुला सेतुओं को लगाने, खरीदारी करते समय कड़े गुण नियंत्रण लागू करने, बेहतर परिरक्षण करने, भराई की मात्रा में कमी करने, मशीनों से सिलाई करने, प्रभावी देख-रेख करने, अचानक छापे मारने और अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण करने/किराए पर लेने जैसे कई एक पग उठाए हैं।

ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को जमीन का आवंटन

809. **श्रीमती रेणुका चौधरी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पंजीकृत ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटन करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समयबद्ध योजना तैयार की है और इस प्रकार एक निश्चित समय का लक्ष्य तय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां

(ख) और (ग) जिन समितियों का 1983 में पंजीकरण हुआ है उन्हें आवंटन के लिए भूमि दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में पालम गांव के निकट पापन कलां के नाम से विख्यात परिसर में अर्जित की गई है। यह योजना दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान, दिल्ली जलपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान इत्यादि जैसे भूमि विकास में लगे विभिन्न सरकारी अभिकरणों के परामर्श से बनाई जा रही है। जैसे ही इस योजना को अन्तिम रूप दे दिया जाता है और इसका अनुमोदन दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा कर दिया जाता है, वैसे ही इन समितियों को उनकी आवश्यकतानुसार भूमि के आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए समाचार पत्रों में एक विज्ञापन जारी किया जाएगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण इस योजना को यथाशीघ्र पूरा करने के प्रयास कर रहा है।

Drought situation in the country

810. SHRI MAHENDRA PRASAD: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what are the states which were in the grip of severe drought this year;

(b) the extent of damage caused to crops, property etc. in each of these states;

(c) whether any central team was sent to visit these drought-affected states to assess the loss and recommend central assistance;

(d) if so, what are the details in this regard;

(e) the amount of central assistance provided to each drought-affected states and what was the amount asked by the states for the purpose; and

(f) what further central assistance is proposed to be provided to these states and by when?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) The States of Andhra Pradesh, Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Tamil Nadu affected by drought during post-monsoon period of 1986-87, have reported continued drought situation during pre-monsoon period of 1987-88. The States of Karnataka and Goa were, however, marginally affected during this period.

(b) A Statement indicating the extent of damages caused due to drought in the States mentioned in part (a) above, is given below as Statement I.